1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित कर ज्वाइंट पेंशन फंड की स्थापना की गई थी। इसमें निवेश के लिए यूएन के महासचिव के प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ भारतीय अधिकारी सुधीर राजकुमार ने बीते दिनों इस्तीफा दे दिया था। यूएन महासचिव ने अब गाजो को अंतरिम प्रतिनिधि नियुक्त किया है।

हर्षवर्धन ने कोरोना की सैंपलिंग व टेस्टिंग रणनीति की समीक्षा की

- कहा, टेस्टिंग किट्स हासिल करने पर पूरा जोर होना चाहिए
- राज्यों को जांच के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर मंत्रिसमूह की उच्चस्तीय बैठक हुई। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार कोरोना वायरस के सैंपल लेने और उसकी जांच करने के लिए अपनाई जा रही रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लैब के लिए तत्काल टेस्टिंग किट्स हासिल करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। हर्षवर्धन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्यों को टेस्टिंग किट्स, रीजेंट या अन्य उपकरणों की कमी न होने पाए। पूर्वोत्तर के राज्यों और लद्दाख समेत उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता देने को कहा है, जहां लैब और जांच की सुविधा नहीं है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार या निजी लैब द्वारा हासिल किए जाने वाले टेस्टिंग किट्स की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग किट्स की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से होते रहना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) द्वारा तत्काल प्रभाव से गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र और प्रोटोकाल तैयार किया जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में आइसीएमआर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक में रीजेंट की खरीद, वेबसाइट इंटीग्रेशन, डाटा प्रबंधन व विश्लेषण, डैशबोर्ड, नियोजित व पूर्ण शोध अध्ययन जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा बताया गया कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त 49 निजी लैब के साथ ही 129 सरकारी लैब काम कर रही हैं, जिनकी प्रतिदिन 13 हजार सैंपल जांच करने की क्षमता है।

आयुष मंत्रालय थेरेपी पर वैज्ञानिक प्रस्ताव मांगेगा

आयुष मंत्रालय ने भारतीय औषधि पद्धति के इस्तेमाल से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने को लेकर वैज्ञानिक प्रस्ताव मंगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर पहल शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना वायरस के लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित आयुर्वेदिक इलाज ढूंढ़ा जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सकों से सुझाव और प्रस्ताव लेने और वैज्ञानिकों द्वारा उसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए एक चैनल बनाने का फैसला किया गया है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक बार चैनल बनने के बाद ही इस बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा।

लॉकडाउन अवधि में निलंबन आदेश सहित अन्य कार्यों की समीक्षा नहीं करेगा केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार लॉकडाउन के दौरान निर्धारित अवधि से पहले निलंबन आदेश और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस स्वीकार करने जैसे विविध कार्यों की समीक्षा नहीं करेगी। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में यह बात कही है। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के फैलने के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर विचार करते हुए केंद्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण अपील एवं नियंत्रण) नियम 1965 और केंद्रीय लोक सेवा (पेंशन) नियम 1972 में निर्दिष्ट समयसीमा का पालन करना संभव नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि उदाहरण के लिए यदि लॉकडाउन शुरू होने पर किसी प्रक्रिया या कार्य को पूरा करने की निर्धारित तारीख 20 दिनों के बाद आती है, तो नियत तारीख लॉकडाउन के दौरान स्थगित रहेगी और लॉकडाउन हटाए जाने के बाद 20 दिन काम पूरा करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन हटाए जाने के बाद अगर काम पूरा करने में 15 दिन से कम समय लगने वाला हो तब प्रक्रिया को 15 दिन के भीतर पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पिछले सप्ताह देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। कोरोना वायरस के कारण देश में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 1200 से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए हैं।

आरोपित के बचाव की समयसीमा तय : मंत्रालय ने कहा कि किसी आरोपित अधिकारी के आरोपपत्र पर बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से निर्णय लेने के बाद चार्जशीट जारी करने की अवधि समाप्त होने से पहले निलंबन आदेश की समीक्षा के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। जांच प्राधिकार के जांच पूरी करने, रिपोर्ट पेश करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस की स्वीकृति एवं अन्य कार्यों के लिए समयसीमा तय है। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा, सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है।

अंतिम तिथि को लॉकडाउन की तारीख के हिसाब से बढ़ाया जाएगा : मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को जारी आदेश में कहा कि जहां सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आती है। ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि को लॉकडाउन के दिनों की संख्या के आधार पर बढ़ाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इसी प्रकार सीसीएस आचार नियम 1964 में निर्धारित सीमा को विभिन्न प्रयोजनों के लिए लॉकडाउन के दिनों की संख्या के आधार पर बढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय कर्मियों को सेवानिवृत्ति में कोई विस्तार नहीं

नई दिल्ली : केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्ति हो रहे लोग इसी दिन रिटायर हो रहे हैं। इनकी सेवानिवृत्ति को कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के चलते टाला नहीं जाएगा। रिटायरमेंट तय समय पर ही होगा फिर चाहे वह लोग वर्क फ्राम होम कर रहे हों या फिर दफ्तर से काम कर रहे हों।

जांच सुविधाएं बढ़ाने को दो सौ से अधिक वैज्ञानिकों ने सरकार से किया आग्रह

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना के कहर के मद्देनजर देश के 200 से अधिक वैज्ञानिकों और अकादमिक बिरादरी के सदस्यों ने सरकार से पूरे देश में कोविड-19 की जांच की सुविधाएं बढ़ाने का आग्रह किया है। वैज्ञानिकों ने यहां जारी एक बयान में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा 21 दिन के लाकडाउन के निर्णय का स्वागत किया है। विभिन्न अकादमिक व शोध संस्थाओं से संबद्ध इन वैज्ञानिकों ने आग्रह किया कि इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार व व्यक्ति विशेष का कोई भी निर्णय या कार्रवाई वैज्ञानिक तार्किकता, कारण, प्रोटोकाल और नियमों के आधार पर ही होना चाहिये।

क्रेंद्र सरकार को संबोधित इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, एजूकेशन एंड रिसर्च के अर्नब घोष, अशोका यूनिवर्सिटी के एल.एस शशिधरा, आइआइटी कानपुर के के. मुरलीधर, दिल्ली विवि से सोनाली सेनगुप्ता और आइआएसईआर कोलकाता के आयन बनर्जी शामिल हैं।

न्यूज गैलरी

देश में फंसे विदेशी सैलानियों के लिए पोर्टल शुरू

नई दिल्ली : देश में फंसे विदेशी सैलानियों की मदद के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया है। इस पर यह जानकारी दी गई है कि वो किन-किन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' नाम से शुरू पोर्टल का मकसद देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी सैलानियों की मदद करना है। बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया आज मुश्किल समय से गुजर रही है। ऐसे समय में सैलानियों खासकर विदेश से आए लोगों की कुशलता सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस पोर्टल पर कोरोना वायरस से जुड़ी हेल्पलाइन या काल सेंटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जहां विदेशी सैलानी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के कंट्रोल सेंटर, संपर्क नंबर के साथ ही राज्य और क्षेत्रीय पर्यटन केंद्रों की जानकारी भी दी गई है। (प्रेट्र)

20 हजार कोचों में होंगे 3.2 लाख आइसोलेशन बेड्स : रेलवे

नई दिल्ली : रेलवे ने मंगलवार को बताया कि कोरोना वायरस मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्डों में तब्दील किए जा रहे 20 हजार कोचों में 3.2 लाख बेड्स होंगे। रेलवे ने इसके लिए अपने 16 जोनों को लक्ष्य दिए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद मुख्यालय को सबसे अधिक 486 कोचों का लक्ष्य दिया गया है। इसके बाद मध्य रेलवे के मुंबई स्थित मुख्यालय को 482 कोचों का लक्ष्य दिया गया है। रेलवे की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, पांच हजार कोचों को आइसोलेशन वार्डों में तब्दील करने का काम शुरू हो गया है। एक कोच में आइसोलेशन के लिए 16 बेड्स होने की संभावना है लिहाजा इन पांच हजार कोचों में 80 हजार बेड्स होंगे। बता दें कि आइसोलेशन वार्डों में तब्दील करने के लिए सिर्फ गैर-वातानुकूलित शयनयान कोचों का चुनाव किया गया है। (प्रेट्र)

सैन्य कर्मियों को सोशल मीडिया पर पहचान नहीं देने की चेतावनी

नई दिल्ली : सेना ने मंगलवार को अपने कर्मियों को आगाह किया कि वे सोशल मीडिया पर अपनी पहचान उजागर नहीं करें और इस सिलसिले में मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन करें। भारतीय सेना के सलाहकार ने कहा कि यह देखा गया है कि सेना के जवान सोशल मीडिया पर अपनी पहचान देते हुए वर्दी में भी वीडियो बना रहे हैं। सभी सैन्य कर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन करें और ऐसी गतिविधियों से परहेज करें। पिछले सितंबर में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने सेवारत और रिटायर सैन्य कर्मियों के नाम पर चलने वाले फर्जी अकाउंटों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद सेना ने अपने कर्मियों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा था। (एएनआइ)

ग्रामीण बेरोजगारों को राहत देगी मनरेगा की संशोधित मजदूरी

दूर होगी परेशानी ▶ मजदूरी में 13 से 32 रुपये की वृद्धि, आज से लागू

लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को भुगतान के लिए धनराशि भी जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक।

कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन में परेशान हो रहे ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा की संशोधित मजदूरी से राहत मिलेगी। मजदूरी की नई की दरें एक अप्रैल यानी बुधवार से लागू हो जाएंगी। कोविड-19 की वजह से चौतरफा बंदी से प्रभावित मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। सरकार इस योजना को कारगर तरीके से लागू करने के लिए पूरा प्रोत्साहन देगी।

मनरेगा की संशोधित मजदूरी सबसे अधिक 32 रुपये महाराष्ट्र में बढ़ी है जहां के मजदूरों को अब 206 रुपये से बढ़कर 238 रुपये मिलेंगे, जबकि सिक्किम, त्रिपुरा, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 192 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 205 रुपये कर दी गई है। यानी केवल 13 रुपये की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मणिपुर में 19 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव है जो बुधवार से लागू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 15 रुपये, जम्मू-कश्मीर में 17 रुपये, पंजाब में 22 रुपये, बिहार व झारखंड में 23 रुपये, हरियाणा व गुजरात में 25 रुपये और मध्य प्रदेश में 14 रुपये की वृद्धि की गई है।

लॉकडाउन से प्रभावित ऐसे परिवारों की बकाया मजदूरी का भुगतान हर हाल में करने के लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश के साथ धनराशि भी जारी कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों के साथ गरीब परिवार के लोगों को केंद्र में रखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया है। आगामी वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा की मजदूरी में की गई वृद्धि को लेकर पिछले दिनों केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज में कुछ घोषणाएं की गई हैं जिससे असमंजस पैदा हुआ। उसमें जो अनुमान लगाया गया है, उसके मुताबिक अगर सौ दिनों तक सभी राज्यों में मनरेगा के मजदूरों ने काम किया है तो उन्हें होने वाली अतिरिक्त आमदनी का हिसाब लगाया गया है।

वर्ष 2019-20 में केंद्र ने मनरेगा के लिए आम बजट में 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसके मुकाबले इस मद में व्यय 71 हजार करोड़ रुपये से अधिक हुआ। इसके मद्देनजर आगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 61,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें वृद्धि होना तय है। तथ्य यह है कि लॉकडाउन से उपजने वाली आर्थिक मंदी को देखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और अधिक धनराशि मनरेगा में आवंटित करनी होगी। इसके लिए सरकार को अलग से तैयारी करनी होगी।

ग्रामीण मांग से वित्तीय व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में भी वृद्धि होनी तय है। उत्तर प्रदेश ने अपने यहां 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के बैंक खाते में उनकी मजदूरी जमा कराई है जो तकरीबन 600 करोड़ रुपये है।

पीएम ने योगासन का वीडियो साझा कर कहा- तनाव घटाने में मिलती है मदद

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के उद्देश्य से किए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को योगासन का एक वीडियो साझा किया और कहा कि यह शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखता है।

मोदी ने वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, 'जब भी समय मिलता है, मैं हफ्ते में एक-दो बार योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करता हूं। इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है, साथ ही यह तनाव और चिंता को भी कम करता है।' उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक-एक वीडियो साझा किया। विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध विवरण के मुताबिक योग निद्रा तनाव कम करने में मदद करता है।

ज्ञात हो कि रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान एक श्रोता ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वह अपनी फिटनेस का कैसे खयाल रखते हैं? इस पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह जल्द ही एक वीडियो पोस्ट करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने योग का जिक्र करते हुए कहा था कि वह न तो फिटनेस विशेषज्ञ हैं और न ही योग प्रशिक्षक, लेकिन योग का अभ्यास कई वर्षों से उनके जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने कहा था, 'कुछ योग आसनों से मुझे बहुत फायदा हुआ है। संभव है कि लॉकडाउन के दौरान इनसे आपको भी कुछ मदद मिल जाए।' इसलिए इसे अपनाएं।

तेलंगाना के सरकारी कर्मियों के वेतन में 75 फीसद तक कटौती

हैदराबाद, एएनआइ : कोरोना वायरस प्रसार के मद्देनजर एक उच्चस्तरीय बैठक में तेलंगाना की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 से 75 फीसद तक कटौती करने का फैसला किया गया।

- मुख्यमंत्री से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी होंगे प्रभावित

प्रगति भवन में आयोजित इस बैठक में फैसला किया गया कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्रियों, विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों, राज्य निगमों के चेयरपर्सनों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के वेतन में 75 फीसद की कटौती की जाएगी। जबकि आइएएस, आइपीएस, आइएफएस और केंद्रीय सेवा के अन्य अधिकारियों के वेतन में 60 फीसद की कटौती होगी। अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में 50 फीसद की कटौती की जाएगी। लेकिन चतुर्थ श्रेणी, आउटसोर्स और अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन में सिर्फ 10 फीसद की कटौती की जाएगी। सभी श्रेणी के पेंशनभोगियों की पेंशन में 50 फीसद की कटौती की जाएगी।

महाराष्ट्र में दो किस्तों में दिया जाएगा मार्च का वेतन

मुंबई, प्रेट्र : लॉकडाउन के कारण पड़ रहे आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का मार्च का वेतन दो किस्तों में देने की घोषणा की है। इस फैसले की वजह केंद्र सरकार से बकाया मिलने में विलंब को बताया गया है। हालांकि पहले राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों समेत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मार्च के वेतन में 60 फीसद की कटौती की जाएगी। 'ए' और 'बी' ग्रेड के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 50 फीसद जबकि 'सी' ग्रेड के कर्मचारियों के वेतन में 25 फीसद की कटौती की जाएगी। वहीं, वरिष्ठ भाजपा नेता आशीष शेलार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस के प्रसार से पैदा हुए हालात से दिन-रात मुकाबला कर रहे पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाए।

सरकार ने कहा- 28 लाख लोगों की एयरपोर्ट और सीपोर्ट पर हो चुकी स्क्रीनिंग

प्रथम पृष्ठ से आगे

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए मेहता ने कहा कि अभी तक 28 लाख लोगों की एयरपोर्ट और सीपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो चुकी है और 3.5 लाख लोगों की निगरानी की जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी फर्जी खबरों से होती है। कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट देख कर कहा कि केंद्र सरकार ने पहचान और इलाज के अलावा बाहर से आना-जाना रोका है। यह भी बताया है कि सरकार एक कमेटी बनाने वाली है जो फर्जी खबरों से निबटेगी। पीठ ने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इनसे डर फैलता है और भय वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 24 घंटे में एक पोर्टल गठित करे जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल हों जो कि कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी दें।

कोरोना की सही तस्वीर के लिए टेस्ट की संख्या बढ़ाना जरूरी : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कमी दूर करने के लिए निजी कंपनियों को जांच किट बनाने की इजाजत दे सरकार
- राज्यों के पास केवल आपात स्थितियों से निपटने के लिए ही टेस्ट किट उपलब्ध हैं

मनीष तिवारी। फाइल

कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से देश में और अधिक कोरोना टेस्ट किट निर्माण की कंपनियों को इजाजत देने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि कोरोना संदिग्ध लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत को अब रोजाना अधिक संख्या में टेस्ट करने की जरूरत है। टेस्ट से ही संदिग्धों की अधिक संख्या में पहचान होगी और भारत कोरोना के स्टेज तीन में जाने की ओर है या हालत नियंत्रण में है इसकी सही तस्वीर इसी से सामने आएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत कोरोना के स्टेज तीन में पहुंच गया है मगर इसकी सही तस्वीर तो टेस्ट से ही सामने आएगी। भारत बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम टेस्ट कर रहा है। लेकिन टेस्टों की संख्या बढ़ाने में दिक्कत यह है कि राज्यों के पास केवल आपात स्थितियों से निपटने के लिए ही कोरोना टेस्ट किट हैं। इसीलिए राज्य इसे जांच प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मनीष तिवारी ने कहा कि अभी केवल चार कंपनियों को किट बनाने की अनुमति है। जबकि 17 कंपनियों ने इसके लिए अप्लाई किया था।

वहीं बरेली में ब्लीचिंग पाउडर के घोल से गरीब मजदूरों को नहलाए जाने की घटना पर क्षोभ जाहिर करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि इस घटना ने भारत और इंडिया में दुर्भाग्यपूर्ण फर्क को दोहराया है। इस लॉकडाउन में एक वर्ग नेटफ्लिक्स देखता है तो दूसरा सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने घरों को पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह स्थिति कहीं से सही नहीं कही जा सकती। सरकार को इस बारे में पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो।

वहीं रिजर्व बैंक के सर्कुलर के बाद भी बैंकों की ओर से तीन महीने तक इएमआई स्थगित करने की अधिसूचना जारी नहीं होने पर चिंता जताते हुए कहा कि वित्तमंत्री को इसके लिए बैंकों को निर्देश जारी करना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस तीन महीने का ब्याज भी माफ करने का आग्रह किया। मनीष तिवारी ने मजदूरों के पलायन से रबी फसल की कटाई और भंडारण की अगले 15 दिनों में आने वाली बड़ी चुनौती पर भी केंद्र सरकार से राज्यों के साथ आपात चर्चा का आग्रह किया।

राहत

कोरोना का प्रसार रोकने के लिए घरेलू उड़ानों के जरिये सामान पहुंचा रही सरकार, चीन से सामान लाने के लिए नई दिल्ली में कार्गो एयरब्रिज स्थापित

शुक्रवार से चीन से आएगा मेडिकल सामान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के बढ़ते के प्रसार को रोकने के लिए जहां सरकार देश में उपलब्ध मेडिकल सामग्री को डोमेस्टिक उड़ानों के जरिये विभिन्न भागों में पहुंचा रही है। वहीं अब उसने इस मुहिम में चीन की मदद लेने का भी निश्चय किया है। शुक्रवार से एयर इंडिया के कार्गो विमान कोरोना से जुड़े मेडिकल उपकरण, सूट, दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर लाने के लिए बीजिंग की उड़ानें भरने लगेंगे। एयर इंडिया ने चीन से कोरोना रोधी सामान लाने के लिए नई दिल्ली में एक कार्गो एयरब्रिज स्थापित किया है।

समूह का गठन : कोरोना से जुड़ी सामग्री जुटाने तथा उसे देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए विमानन मंत्रालय ने अधिकारियों एवं संबंधित पक्षकारों के एक समूह का गठन किया है। समूह की देखरेख में एयर इंडिया, एलायंस एयर, वायुसेना के अलावा प्राइवेट एयरलाइनों की ओर से हब एंड स्पोक लाइफलाइन कार्गो सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में हब जबकि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, अगरतला, आइजोल, इंफाल, कोयंबटूर तथा तिरुअनंतपुरम में स्पोक बनाए गए हैं। हब एंड स्पोक पद्धति में कुछ बड़े शहरों को पहिये की धुरी के केंद्र, जबकि छोटे शहरों को तीलियों के छोर की भांति क्षेत्रीय खपत स्थलों के तौर पर चिह्नित करके सामान की आवाजाही सुनिश्चित की जाती है।

अब तक 62 कार्गो उड़ानें : विमानन मंत्रालय के अनुसार पिछले पांच दिनों में कार्गो विमान सेवाओं के जरिये देश के तमाम इलाकों में दवाएं, मेडिकल उपकरण, सूट, मास्क और सैनिटाइजर आदि पहुंचाने के लिए एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, इंडिगो और स्पाइसजेट के विमानों ने कुल 62 उड़ानें भरी हैं।

रेलवे ने शुरू की पार्सल सेवाएं : रेलवे भी पार्सल सेवाओं के मार्फत रोजमर्रा का जरूरी सामान पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाने में जुटा गया है। इसके लिए अनेक लंबी दूरी की पार्सल कार्गो एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेनें टाइम टेबल के हिसाब से पैसेंजर ट्रेनों की भांति चलेंगी। इनके अलावा मालगाड़ियों के जरिये अनाज, दालें, खाद्य तेल, फल-सब्जी, नमक, खाद के अलावा पेट्रोलियम उत्पाद, स्टील, सीमेंट और कोयले को पहले पहुंचाया जा रहा है।

सड़क मंत्रालय ने दी छूट : सड़क के रास्ते सामान ढुलाई की रफ्तार तेज करने के लिए हाईवे पर टोल बंदी तथा थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम अदायगी में ढील देने के बाद अब सरकार ने 30 जून तक वाहनों के कागजात रिन्यू कराने की जरूरत से छूट देने का एलान कर दिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि क्रूड की घटती कीमतों को देखते हुए सरकार को कोरोना राहत पैकेज के तौर पर पेट्रोल, डीजल के अलावा टायरों के दाम घटाने का एलान भी करना चाहिए। परिवहन लागत घटने से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का कमजोर मनोबल बढ़ेगा।

लॉकडाउन के दौरान बढ़े घरेलू हिंसा के मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन महिलाओं के लिए बंदी में बदल गया है। इस दौरान पति द्वारा अपना गुस्सा पत्नी पर उतारने के चलते घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को 23 मार्च से 30 मार्च तक घरेलू हिंसा की 58 शिकायतें मिलीं। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि इनमें से अतिकतर शिकायतें उत्तर भारत खासकर पंजाब से आई हैं।

शर्मा ने कहा कि शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। पुरुष घर बैठे निराश हो रहे हैं और महिलाओं पर कुंठा निकाल रहे हैं। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से पंजाब में देखी जा रही है, जहां से हमें ऐसी कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि राज्य से सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ई-मेल पर हमें 58 शिकायतें मिली हैं। असली आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि समाज के निचले तबके की महिलाएं हमें डाक द्वारा अपनी शिकायतें भेजती हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी